

पैन पावर

हिंदी दैनिक समाचार पत्र



वर्ष - 1 अंक - 81

मंगलवार, अक्टूबर 06, 2026

विशाखापट्टनम संपादक: गंट्यादा अप्पाराव

पृष्ठों. 4मूल्य. 1रु

कमर्शियल विभाग में आखिर किसका राज?

‘अम्मा’ का – या नियमों का?

विशाखापट्टनम पोर्ट में बर्थ आवंटन, जहाजों की शिप्टिंग, एजेंटों पर कथित दबाव और निर्णय प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल क्या कमर्शियल विभाग के अहम फैसलों पर एक ही अधिकारी का असामान्य प्रभाव है?

क्या जहाज को बर्थ दिलाने के लिए कोई कथित अनौपचारिक ‘रेट’ तय है?

क्या कथित मांग पूरी न करने पर जहाजों को एंकरिज भेजने का दबाव बनाया जाता है?

अहनलाइन व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद एजेंटों को व्यक्तिगत रूप से मिलने की जरूरत क्यों पड़ती है?

पैसे में हिस्सेदारी को लेकर कथित तौर पर जिन ”ऊपर वालों“ का नाम लिया जाता है, वे आखिर कौन हैं?

‘ग्रीन एनर्जी’ फाइल के पीछे असली कहानी क्या है?

क्या विजिलेंस व्यवस्था वास्तव में प्रभावी ढंग से काम कर रही है?

और पूर्व में कथित सीबीआई कार्रवाई को लेकर चल रही चर्चाओं में कितनी सच्चाई है?

‘पैन पावर’ इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड रिपोर्ट। एपिसोड्व – २

इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क, पैन पावर

विशाखापट्टनम, 4 अक्टूबर:

विशाखापट्टनम पोर्ट के कर्माशियल विभाग में महत्वपूर्ण फैसलों पर आखिर किसका नियंत्रण है?

क्या सभी निर्णय निर्धारित नियमों, दर्ज प्रक्रियाओं और संस्थागत निगरानी के तहत लिए जा रहे हैं? या फिर निर्णय प्रक्रिया पर एक ही अधिकारी का प्रभाव जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है? पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र से जुड़े कुछ वर्गों में फिलहाल यही गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

इन चर्चाओं के केंद्र में एक नाम से ज्यादा एक संबोधन बार–बार सुनाई दे रहा हैकू “अम्मा”

पैन पावर इन सभी आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। लेकिन आरोपों की गंभीरता और एक प्रमुख सार्वजनिक संस्था की साथ से जुड़े संभावित प्रभाव को देखते हुए इन सवालों की दस्तावेजी जांच और आधिकारिक जवाब जरूरी है।

क्या एक व्यक्ति के नियंत्रण में है कमर्शियल विभाग?

विभाग की कार्यप्रणाली से परिचित कुछ सूत्रों का आरोप है कि महत्वपूर्ण कमर्शियल फैसलों पर एक ही अधिकारी का प्रभाव सामान्य प्रशासनिक जिम्मेदारी से कहीं अधिक हो सकता है। सवाल उठ रहे हैंकू कौन–सी फाइल पहले आगे बढ़े? कौन–सी फाइल लंबित रहे? किसे पहले मंजूरी मिले?

किस एजेंट को इंतजार कराया जाए? किस जहाज को बर्थ में प्राथमिकता मिले?

यह मामला केवल एक अधिकारी की कार्यशैली या दपत्तर की आंतरिक व्यवस्था का नहीं है। मुख्य सवाल यह है कि क्या नि्धारित निर्णय प्रक्रिया का समान रूप से पालन हो रहा है? क्या वरिष्ठ अधिकारियों तक पूरी और सही जानकारी पहुंच रही है?

यदि सभी फैसले नियमों के तहत हो रहे हैं, तो आधिकारिक रिकॉर्ड इसे स्पष्ट कर सकते हैं। क्या बर्थ के लिए कोई ‘रेट’ तय है? सबसे गंभीर आरोपों में से एक जहाजों के बर्थ आवंटन से जुड़ा है।

कुछ सूत्रों का आरोप है कि कुछ जहाजों को बर्थ दिलाने या बर्थ पर बनाए रखने के बदले कथित तौर पर अनौपचारिक आर्थिक मांग की जाती है।

पैन पावर ने किसी तय ‘रेट’ की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है।

लेकिन सवाल गंभीर हैं।

क्या किसी शिपिंग एजेंट से अनधिकृत भुगतान की मांग की गई? कथित मांग किसने की? क्या ऐसा भुगतान का बर्थ प्राथमिकता से कोई संबंध था?

क्या किसी निजी बातचीत के बाद किसी जहाज को विशेष सुविधा मिली?

इन सवालों का जवाब अफवाहों से नहीं, बल्कि रिकॉर्ड से मिल सकता है।

बर्थ आवंटन, जहाज आगमन डेटा, एजेंट कम्युनिकेशन, मंजूरी का समय, आंतरिक नोटिंग और निर्णयों की समय–श्रृंखला की जांच जरूरी है।

“हिस्सा ऊपर तक जाता है” कृ आखिर ये ‘ऊपर वाले’ कौन? एक और गंभीर आरोप कथित बयानों से जुड़ा है कि एकत्र किया गया पैसा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि “ऊपर वालों” तक हिस्सा पहुंचाया जाता है।

पैन पावर ने इस कथित बयान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है।

लेकिन यदि कोई एजेंट, ठेकेदार या संबंधित पक्ष रिकॉर्ड पर यह कहता है कि ऐसी बात कही गई थी, तो इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

ये “ऊपर वाले” कौन हैं?

क्या वरिष्ठ अधिकारी वास्तव में इसमें शामिल हैं?

या उनके नाम का इस्तेमाल बिना जानकारी के एजेंटों पर दबाव

बनाने के लिए किया जा रहा है?

दोनों स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इसलिए निष्पक्ष जांच को अनुमान नहीं, बल्कि तथ्यों और संभावित धन–प्रवाह के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए।

यदि कोई धन–प्रवाह नहीं है, तो वह भी सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए।

पैसे दो और बर्थ पर रहो? इंकार करो तो एंकरिज?

एक और आरोप जहाजों पर ऑपरेशनल दबाव से जुड़ा है।

सूत्रों के मुताबिक कुछ एजेंटों को इस तरह की टिप्पणियों का सामना करना पड़ता हैकू

“कार्गो हैंडलिंग धीमी है।”

“प्रदर्शन ठीक नहीं है।”

“ऑपरेशन संतोषजनक नहीं है।”

ऐसी टिप्पणियां सही भी हो सकती हैं, यदि वे वास्तविक परिचालन

आंकड़ों पर आधारित हों।

लेकिन सवाल यह हैकू

क्या यही मानक हर जहाज पर सामान रूप से लागू होते हैं? या कथित अनौपचारिक मांगों और जहाज को बर्थ पर रखने

अथवा एंकरिज भेजने के फैसलों के बीच कोई संबंध है?

किसी जहाज को बर्थ से एंकरिज भेजे जाने पर शिपिंग कंपनी को समय, ईंधन और संचालन लागत में भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए वेसल परफॉर्मंस रिपोर्ट, कार्गो हैंडलिंग डेटा, बर्थ उत्पादकता रिकॉर्ड, शिपिंग आदेश और एंकरिज रिकॉर्ड की संयुक्त जांच जरूरी है।

तभी पता चलेगा कि फैसले वस्तुनिष्ठ थे या मनमाने।

जब व्यवस्था ऑनलाइन है तो व्यक्तिगत मुलाकात क्यों?

एजेंटों की ओर से मंजूरी और हस्ताक्षर में कथित देरी को लेकर

भी सवाल उठ रहे हैं।

सवाल सीधा है।

यदि आवेदन पूरा है

दस्तावेज पूरे हैं

प्रक्रिया ऑनलाइन है

तो फिर किसी विशेष अधिकारी से

व्यक्तिगत मुलाकात क्यों जरूरी हो?

कुछ मामलों में स्पष्टीकरण या सत्यापन के लिए व्यक्तिगत बातचीत आवश्यक हो सकती है।

लेकिन यदि व्यक्तिगत मुलाकात एक ‘अनलिखा नियम’ बन गई है, तो प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों है।

एक पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य विवेकाधीन हस्तक्षेप कम

करना होना चाहिए, न कि एक नया अनौपचारिक चरण जोड़ना।

क्या जुनियर कर्मचारियों से निजी जांच जरूरी है?

एक और आरोप निचले स्तर के कर्मचारियों से जुड़ा है।

कुछ सूत्रों का दावा है कि उनसे आधिकारिक काम के बजाय

निजी कार्य करवाए जाते हैं।

इस आरोप की भी दस्तावेजी जांच जरूरी है।

सच्चाई इन रिकॉर्ड से सामने आ सकती हैकू

– उपस्थिति रजिस्टर

– ड्यूटी रोस्टर

– वाहन लॉगबुक

– गेट एंट्री रिकॉर्ड

– एजेंट कम्युनिकेशन रजिस्टर

– सीसीटीवी फुटेज

यदि सभी कर्मचारी केवल सरकारी काम में लगे थे, तो

रिकॉर्ड इसे साबित कर देंगे।

यदि सरकारी संसाधनों या कर्मचारियों का निजी इस्तेमाल हुआ,

तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

‘ग्रीन एनर्जी’ फाइल में आखिर क्या है?

कमर्शियल विभाग से जुड़ी चर्चाओं में एक और मुद्दा बार–बार

सामने आ रहा हैकू

“ग्रीन एनर्जी”

पैन पावर इस प्रोजेक्ट और कमर्शियल

विभाग की भूमिका से जुड़े सवालों की पड़ताल कर रहा है।

कैम–सी कंप्नी या संस्था इससे जुड़े हैं

प्रस्ताव क्या था?

फाइल किसने शुरू की?

किसने सिफारिश की?

किसने मंजूरी दी?

या किसी तरह की विशेष सुविधा,



रियायत, प्राथमिकता या व्यावसायिक लाभ दिया गया?

उसका दर्ज आधार क्या था?

पूरी फाइल देखे बिना कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

लेकिन यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है, तो निर्णय प्रक्रिया का रिकॉर्ड सभी संदेह दूर कर

सकता है।

एजेंट खुलकर बोलने से क्यों डर रहे हैं?

सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक यह है कि कुछ शिपिंग एजेंट और संबंधित हितधारक खुलकर बोलने से हिचक क्यों रहे हैं?

क्या उन्हें गवियं में नुकसान का डर है? क्या अंगला जहाज देर से बर्थ पाएगा?

क्या मंजूरी रोक दी जाएगी?

क्या ऑपरेशनल फैसले प्रतिकूल हो सकते हैं?

ऐसा डर वास्तविक हो या केवल धारणा, दोनों ही स्थितियों में संस्था की साथ

को नुकसान पहुंचता है।

पोर्ट अथॉरिटी को ऐसी गोपनीय शिकायत व्यवस्था पर

विचार करना चाहिए जहां एजेंट बिना प्रतिशोध के डर

के जानकारी दे सकें।

विजिलेंस: सक्रिय निगरानी या केवल औपचारिक व्यवस्था?

विशाखापट्टनम पोर्ट में विजिलेंस व्यवस्था मौजूद है।

लेकिन उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

क्या शिकायतों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है?

क्या ईमेल का जवाब मिलता है?

क्या फोन पर दी गई शिकायतें दर्ज होती हैं?

क्या शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी मिलती है?

कमर्शियल विभाग से संबंधित कितनी शिकायतें आईं?

कितनी बंद की गईं?

कितनों पर जांच हुई?

कितने मामलों में कार्रवाई हुई?

इन आंकड़ों से अफवाहों की तुलना में कहीं ज्यादा स्पष्ट तस्वीर

मिल सकती है।

यदि फोन और ईमेल काम नहीं करने के आरोप गलत हैं तो पोर्ट प्रशासन

को सही शिकायत माध्यम सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने चाहिए।

कथित सीबीआई रेड कृ तथ्य, अफवाह या गलत प्रचार?

पोर्ट सर्फिकल में सबसे गंभीर दावों में से एक यह है कि ‘अम्मा’ के नाम से पहचानी जा रही अडि

कारी का अतीत में किसी सीबीआई रेड या कार्रवाई से

कथित संबंध रहा है।

पैन पावर ने इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है।

इसलिए इसे स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

लेकिन सवाल पूछे जाने चाहिएकू क्या वास्तव में कोई सीबीआई

तलाशी, रेड या जांच हुई थी?

यदि हां, तो किस वर्ष?

किस कैस नंबर या कार्यक्षेत्र के तहत? आरोप क्या थे?

क्या कुछ जब्त किया गया?

क्या आरोपजन दाखिल हुआ?

क्या मामला बंद हो गया?

क्या विभागीय कार्रवाई हुई?

या यह पूरा दावा केवल पोर्ट के भीतर चल रही

अपुष्ट चर्चा है?

जवाब गलियारों की चर्चा से नहीं, आधिकारिक रिकॉर्ड से आना चाहिए।

रिकॉर्ड बोलेंगे

सच्चाई केवल गुमनाम आरोपों पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए।

निम्न रिकॉर्ड की पारदर्शी जांच

महत्वपूर्ण जवाब दे सकती हैकू

– बर्thing प्रोग्राम

– वेसल अराइवल रिकॉर्ड

– बर्थ अलॉटमेंट डेटा

– वेसल परफॉर्मंस रिपोर्ट

– कार्गो हैंडलिंग आंकड़े

– एंकरिज और शिपिंग आदेश

– शिपिंग एजेंट कम्युनिकेशन

– आंतरिक फाइल मूवमेंट

– वाहन लॉगबुक

– मंजूरी के समय का रिकॉर्ड

– विजिटर रजिस्टर

– उपलब्ध और कानूनी रूप से सुरक्षित सीसीटीवी रिकॉर्ड

– वाहन लॉगबुक

– विजिलेंस शिकायत रिकॉर्ड

– संबंधित ‘ग्रीन एनर्जी’ फाइल और मंजूरियां

इन रिकॉर्ड की समय–आधारित तुलना कई अहम सवालों के

जवाब दे सकती है।

क्या फैसले समान मानकों पर लिए गए?

क्या कुछ जहाजों के साथ अलग व्यवहार किया गया?

क्या मंजूरी में असामान्य देरी हुई?

क्या निजी मुलाकातों के बाद निर्णय बदले?

क्या किसी व्यक्ति ने दस्तावेजी अडि

कार–श्रृंखला से बाहर प्रभाव डाला? पोर्ट प्रशासन के सामने सबसे

बड़ा सवाल

यह मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं है।

यह संस्थागत विश्वसनीयता का

सवाल है।

क्या कमर्शियल विभाग के फैसले नियम–आधारित हैं?

क्या बर्थ आवंटन पारदर्शी है?

क्या जहाजों के प्रदर्शन के मानक सभी पर समान रूप से लागू होते हैं?

क्या एजेंट बिना अनौपचारिक दबाव के काम कर सकते हैं?

क्या वरिष्ठ अधिकारियों को नीचे लिए जा रहे हर महत्वपूर्ण फैसले

की जानकारी है?

क्या विजिलेंस स्वतंत्र और प्रभावी है?

और कथित वसूली, प्रभाव या पक्षपात के आरोपों के पीछे कोई

वास्तविक सबूत है?

यदि आरोप निराधार हैं, तो पोर्ट अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड के

जरिए उन्हें खारिज करने का पूरा अवसर है।

यदि दस्तावेजी सबूत किसी आरोप की पुष्टि करते हैं, तो जिम्मेदारी

तय होनी चाहिएकू चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों न हो।

पैन पावर विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और संबं

धित अधिकारियों की आडि

कारिक प्रतिक्रिया को पूर्ण रूप से या उचित संदर्भ में

प्रकाशित करने के लिए तैयार है।

अगले एपिसोड – 3 में

‘अम्मा’ के पीछे कौन?

किन जहाजों को बर्थ से एंकरिज भेजा गया कृ और क्यों?

एजेंटों के पास कथित तौर पर कौन से दस्तावेज और कम्युनिकेशन मौजूद हैं?

‘ग्रीन एनर्जी’ फाइल पर किनके हस्ताक्षर हैं?

“ऊपर वालों की हिस्सेदारी” वाले आरोप के पीछे कोई सबूत है?

विजिलेंस रिकॉर्ड क्या बताते हैं?

और कमर्शियल विभाग से जुड़े आरोपों पर आधिकारिक फाइलें क्या कहती हैं?

पैन पावर इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क और दस्तावेज। और सवाल। और जवाब।

एपिसोड – 3 में जारी

रायलसीमा विकास सभा

में राजनीति नहीं: पवन कल्याण



(पैन पॉवर न्यूज):

कडपा, 5 अक्टूबर: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कडपा जिले के प्रोहटूर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधिात करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने वार्डएसआरसीपी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने केंद्र से मिले

धन का उचित उपयोग नहीं किया। पवन कल्याण ने याद दिलाया कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन को फिर से विस्तार दिया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनके आक्रोश और उत्साह को समझते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह राजनीति की बात करने का समय नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि

रायलसीमा विकास सभा में राजनीति को जगह नहीं दी जानी

संपादकीय

2050 तक वृद्ध भारत

एक समय भारत को दुनिया एक युवा देश के रूप में देखती थी। विशाल युवा आबादी, कामकाजी उम्र के लोगों की बड़ी संख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाकृ इन सभी को भारत की जनसांख्यिकीय ताकत माना जाता था। लेकिन समय बदल रहा है। जन्मदर घट रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और परिवारों का आकार छोटा हो रहा है। परिणामस्वरूप युवा भारत धीरे-धीरे वृद्ध भारत में बदल रहा है। क्या हम समृद्ध देश बनने से पहले ही वृद्ध देश बन रहे हैं? यह सवाल अब केवल चिंता का विषय नहीं रह गया है, बल्कि देश के भविष्य को नि्ध ारित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 10.38 करोड़ थी। सरकारी अनुमानों के अनुसार 2021 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 13.79 करोड़ हो गई। 2031 तक इसके 19.38 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। कुल आबादी की वृद्धि की तुलना में वृद्ध आबादी का अधिक तेजी से बढ़ना इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (न्छथ्‍) के अनुमानों के अनुसार, 2050 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या कुल आबादी के 20 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। यानी लगभग हर पांच भारतीयों में से एक व्यक्ति वृद्ध हो सकता है। एक अन्य अनुमान के अनुसार 2050 तक देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 34.6 करोड़ तक पहुंच सकती है। 80 वर्ष और उससे अधिाक आयु वाले अति—वृद्ध लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ने वाली है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में चुनौती केवल वृद्ध लोगों की बढ़ती संख्या तक सीमित नहीं होगी। दीर्घकालिक चिकित्सा, देखभाल, आर्थिक सुरक्षा, अकेलापन, दिव्यांगता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे अनेक मुद्दे भी देश के सामने आएंगे। भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव के पीछे प्रमुख कारण घटती प्रजनन दर है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की कुल प्रजनन दर प्रति महिला औसतन 1.9 बच्चे थी। यह पीढ़ियों की जगह लेने के लिए आवश्यक 2.1 के स्तर से कम है। दूसरी ओर, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं, शिशु मृत्यु दर में कमी और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। एक ओर बच्चों के जन्म की संख्या घट रही है, वहीं दूसरी ओर अधिक लोग लंबा जीवन जी रहे हैं। ये दोनों बदलाव मिलकर भारत की आयु संरचना को मूल रूप से बदल रहे हैं। यह बदलाव विकास के खिलाफ कोई नकारात्मक संकेत नहीं है। लोगों का अधिाक समय तक स्वस्थ जीवन जीना वास्तव में चिकित्सा और सामाजिक प्रगति का संकेत है। वर्तमान समय में भारत के पास कामकाजी उम्र की बड़ी आबादी है। इसी चरण में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करना आवश्यक है। क्योंकि आज काम कर रहा युवा ही कल के वृद्ध भारत का आर्थिक आधार बनेगा। वृद्धावस्था आने के बाद उसके बारे में सोचना बहुत देर हो जाएगी। वृद्ध समाज की नींव युवा अवस्था में ही रखनी होगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुमानों के अनुसार 2046 तक भारत में वृद्ध लोगों की संख्या 0 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या से अधिक हो सकती है। यह भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। देश को अभी से इसके लिए तैयार होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत के सामने अब एक और बड़ी चुनौती है। यह केवल बड़ी आबादी का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि बदलती जनसांख्यिकीय संरचना का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना भी है। अब देश के विकास को केवल सकल घरेलू उत्पाद (लक्‍) की वृद्धि दर से मापना पर्याप्त नहीं होगा। कोई देश अपने वृद्ध नागरिकों को कितनी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह भी विकास का एक महत्वपूर्ण पैमाना होना चाहिए। वृद्धावस्था भविष्य की समस्या नहीं हैय यह पहले से ही शुरू हो चुकी वर्तमान वास्तविकता है। समृद्ध होने से पहले वृद्ध राष्ट्र बन जाना अनिवार्य रूप से त्रासदी नहीं है। लेकिन देश के संपन्न होने की प्रक्रिया के दौरान वृद्धावस्था के लिए तैयारी न करना ही वास्तविक खतरा है। भारत केवल युवा देश की अपनी पुरानी पहचान के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकता। कल के वृद्ध भारत को ६ यान में रखते हुए आज ही स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन, दीर्घकालिक देखभाल, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शहरी नियोजन और परिवार—आधारित सहायता प्रणालियों को नए सिरे से तैयार करना होगा। अन्यथा, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत समृद्ध देश बनने से पहले ही वृद्ध राष्ट्र बनने के विरोधाभास का सामना कर सकता है। इसलिए अभी से जागरूक होने और जनसांख्यिकीय बदलाव को बोझ के बजाय अग्रिम योजना के संकेत के रूप में देखने की जरूरत है। युवा भारत के निर्माण के साथ—साथ सम्मानजनक वृद्ध भारत के निर्माण को भी समान महत्व देना होगा। यही समावेशी और समग्र विकास का वास्तविक अर्थ है।

हिंसा के अलावा और है ही क्या?

पिछले 600 वर्षों में ऐसा कब हुआ है जब पश्चिमी देशों के गठबंधन ने दुनिया के बाकी देशों पर हिंसा न की हो? क्षेत्र के लिए, संसाधनों के लिए, गुलामों के लिए, बाजारों के लिए और प्रभुत्व के लिए। युद्ध के दौरान भी और युद्ध न होने के समय भी। यहां तक कि आपसी प्रभुत्व के लिए लड़े गए युद्धों में भी भारत समेत अन्य देशों के युवाओं को जबरन अपनी सेनाओं में भर्ती कर उन्हें बलिदान करने से वे कब रुके हैं? पिछले 600 वर्षों के संघर्षों और युद्धों में उनकी हिंसा के कारण कितने करोड़ लोग मारे गए? उनके शोषण से पैदा हुए अकाल, भुखमरी और हिंसा का शिकार कितने लोग हुए? जिस लोकतंत्र का वे उपदेश देते हैं, क्या वह स्वयं एक छल और हिंसा का रूप नहीं है? क्या वह उनके निरंतर शोषण पर पड़ा हुआ एक पर्दा नहीं है? अपने मूल स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा और उसकी संस्थाएं अत्यंत उत्कृष्ट हैं। लोग अपने कल्याण के लिए वास्तव में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। पश्चिमी दार्शनिकों ने भी लोकतंत्र को विस्तार और गहराई से परिभाषित किया है। जब नवसलवादियों ने कहा कि 'बंदूक की नली से ही सत्ता निकलती है', तो उनकी कड़ी आलोचना हुई। उन्हें हिंसावादी कहा गया और उनका दमन किया गया। यह सही भी था। जब जनता की राय को प्रतिबिंबित करने के लिए लोकतांत्रिक मतदान व्यवस्था मौजूद है, तो ऐसे रास्ते की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र होने का दावा करने वाला अमेरिका क्या कर रहा है? और आधुनिक लोकतंत्र की जन्मभूमि होने का दावा करने वाले ब्रिटेन तथा कई यूरोपीय देश पिछले 600 वर्षों से क्या करते आए हैं? अपने स्वार्थों के लिए हथियार जुटाने और दूसरों पर हिंसा करने के अलावा उन्होंने किया ही क्या है? उनका पूरा इतिहास हिंसक रहा है। आज भी हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान को हथियारों की धमकी दिए बिना शायद ही एक सप्ताह गुजरता है। हमलों की तो बात ही अलग है। वे बार—बार चेतावनी देते हैं कि पूरे ईरानी राष्ट्र और उसकी संस्कृति को रातोरात मिटाया जा सकता है। वे अक्सर दुनिया को याद

दिलाते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है और उसके पास ऐसी तबाही मचाने वाले हथियार मौजूद हैं। हिंसा के अलावा और है ही क्या? लोकतांत्रिक तरीके से आगे आता है और शांतिपूर्ण समझ के लिए बातचीत की मेज पर बैठता है। बातचीत चलती है। मध्यस्थ यह भी घोषणा करते हैं कि वार्ता संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी अचानक, बातचीत के बीच ही अमेरिका और इजरायल मिलकर तेहरान पर बमबारी करते हैं। ईरान के नेता को उनके परिवार के सदस्यों के साथ मार दिया जाता है। दुनिया स्तब्ध रह जाती है। दोनों देश अपनी कार्रवाई का कारण स्पष्ट नहीं करते। हिंसा के अलावा और है ही क्या? मीडिया कारणों को लेकर अटकलें लगाता है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी जुटाई जाती है। युद्ध विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि इजरायल को बातचीत और लोकतांत्रिक समाधान वास्तव में पसंद नहीं हैं। वे यह भी कहते हैं कि इजरायल ने ईरान के नेता की हत्या की रणनीति इसलिए बनाई कि वहां की व्यवस्था भी उसी तरह आत्मसमर्पण कर दे, जैसे कथित तौर पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को एक आधे रात के सैन्य अभियान में पकड़कर ले जाया गया था और सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बाद वहां की सरकार को झुकना पड़ा था। इन विश्लेषणों के अनुसार इजरायल ने ट्रंप को इसके लिए राजी किया और ऐसा हमला किया। इस पूरे घटनाक्रम में हिंसा के अलावा और क्या है? अमेरिका के पास हजारों परमाणु हथियार हैं। इजरायल के पास लगभग सौ हैं। नाटो देशों के पास कई सौ और हैं। इन शक्तियों के कई मित्र देश शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु अनुसंधान करते हैं और ये शक्तियां उनका सहयोग करती हैं। हाल ही में सऊदी अरब को भी इसी तरह की सहायता का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन ईरान के लिए वे किसी भी अवसर को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वे केवल परमाणु हथियारों का विरोध नहीं करते, बल्कि शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग की संभावना को भी नकारते हैं। जब ईरान में उनके अनुकूल शासक सत्ता में था, तब परमाणु रिएक्टर उपलब्ध कराने वाले



भी वही थे। लेकिन जब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाले शासक सत्ता में आए, तो सारे सिद्धांत उलट गए। नई सरकार बार—बार कहती रही है कि उसका परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के लिए नहीं है। इजरायल ने भले ही परमाणु अप्रसार संधि (छच्‍) पर हस्ताक्षर न किए हों, लेकिन ईरान ने किया है। वह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने परमाणु अनुसंधान केंद्रों की नियमित जांच की अनुमति देता है। खामेनेई ने भी कथित तौर पर एक से अधिक बार फतवा जारी किया है कि परमाणु हथियार जैसे सामूहिक विनाश के हथियार बनाना इस्लाम के विरुद्ध है और इसलिए उनका उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए। जो भी हो, ईरान में ऐसी सरकार है जो उनके निर्देशों के अनुसार नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम करती है। वह अपने विशाल तेल और गैस भंडार उनकी कंपनियों को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सौ तरह के बहाने खोजकर हमले करना जरूरी समझा जाता है। इसमें कसम—कदम पर हिंसा के अलावा और क्या दिखाई देता है? ईरान ने अमेरिका के साथ कभी कुछ नहीं किया था। वहां की जनता अपने ऊर्जा संसाधनों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी और 1953 में ब्रिटिश कंपनियों के नियंत्रण में मौजूद संसाधनों को अपने अधिकार में ले लिया। वह ब्रिटेन—विरोधी कदम था, अमेरिका—विरोधी नहीं। फिर भी अमेरिकी सीआईए

ने ब्रिटेन के साथ मिलकर उस सरकार को गिरा दिया। उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया। इसे सहन न करने वाले लोगों ने अंततः उस शाह को सत्ता से हटा दिया जिसे फिर से सत्ता में लाया गया था। उस समय से शुरू हुई अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की साजिशें आज तक जारी हैं। ऐसे हमले और विनाश नहीं हैं जो उन्होंने न किए हों। हजारों नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। आज भी वही सिलसिला जारी है। उनका कहना है कि यदि ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो वे जब तक चाहें तब तक विनाश जारी रखेंगे। वे खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि वे आने वाली पीढ़ियों के नेताओं को खत्म कर सकते हैं। इसे हिंसा के अलावा और क्या कहा जाए? और इस पूरे अन्याय में बलि चढ़ रहे फिलिस्तीन की बात क्या है? वह एक स्वतंत्र देश है। द्वितीय विश्व युद्ध तक इजरायल नाम का कोई ऐसा राज्य नहीं था। उस समय पश्चिमी शक्तियों ने इसे नए सिरे से बनाया। इसके लिए फिलिस्तीन का विभाजन किया गया। कहा गया कि फिलिस्तीन और इजरायल दो स्वतंत्र देशों के रूप में एक—दूसरे के साथ रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन उसके बाद के दशकों में क्या हुआ? इजरायल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र और टिकाऊ देश के रूप में अस्तित्व में रहे। अमेरिका भी ऐसा नहीं चाहता। उनका

लक्ष्य एक ऐसा 'ग्रेटर इजरायल' है जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा हो। इसके लिए गाजा को तबाह किया जाता है और बड़े पैमाने पर हत्याएं की जाती हैं। अमेरिका इजरायल को हथियार और धन उपलब्ध कराता है। यूरोपीय देश हथियारों का हस्तांतरण करते हैं और व्यापार के माध्यम से वित्तीय सहायता देते हैं। इजरायल को नियंत्रित करने वाले प्रस्तावों को सुरक्षा परिषद में वीटो किया जाता है। नेतन्याहू को दोषी ठहराने वाली अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्था पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। न्यायाधीशों को धमकाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में हिंसा कहां नहीं है? इजरायल वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करता जा रहा है। वहां हमलों के जरिए फिलिस्तीनियों को उनके घरों से खदेड़ते हुए हजारों यहूदियों के लिए बस्तियां बसाई जा रही हैं। बसने वालों की हिंसा को सेना के माध् यम से समर्थन दिया जाता है। इन बस्तियों को धन दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया और इसकी निंदा किए जाने के बावजूद इसकी अनदेखी की जाती है। राजधानी को तेल अवीव से बदलकर वेस्ट बैंक में स्थित यरुशलम ले जाने के कदम को ट्रंप स्वीकार करते हैं। वे बस्तियों को भी खारिज नहीं करते। मानवाधिकार संगठन और यहां तक कि निष्पक्ष पश्चिमी मीडिया संस्थान भी वेस्ट बैंक

में हो रही हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर भी कुछ नहीं रुकता। हिंसा कहां नहीं हो रही है? जैसा कि शुरुआत में कहा गया, पिछले 600 वर्षों में ऐसा कब हुआ है जब पश्चिमी देशों के गठबंधन ने दुनिया के बाकी देशों पर हिंसा न की हो? क्षेत्र के लिए, संसाधनों के लिए, गुलामों के लिए, बाजारों के लिए और प्रभुत्व के लिए। युद्ध के दौरान भी और युद्ध न होने के समय भी। यहां तक कि आपसी प्रभुत्व के लिए लड़े गए युद्धों में भी भारत समेत अन्य देशों के युवाओं को जबरन अपनी सेनाओं में भर्ती कर उन्हें बलिदान करने से वे कब रुके हैं? पिछले 600 वर्षों के संघर्षों और युद्धों में उनकी हिंसा के कारण कितने करोड़ लोग मारे गए? उनके शोषण से पैदा हुए अकाल, भुखमरी और हिंसा का शिकार कितने लोग हुए? जिस लोकतंत्र का वे उपदेश देते हैं, क्या वह स्वयं एक छल और हिंसा का रूप नहीं है? क्या वह उनके निरंतर शोषण पर पड़ा हुआ एक पर्दा नहीं है? अपने मूल स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा और उसकी संस्थाएं अत्यंत उत्कृष्ट हैं। लोग अपने कल्याण के लिए वास्तव में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। पश्चिमी दार्शनिकों ने भी इसे विस्तार और गहराई से परिभाषित किया है। लेकिन साम्राज्यवादियों ने इसी विचार को हिंसा के एक निरंतर चक्र में बदल दिया है। उन्होंने हिंसा और युद्ध को अपनी विदेश नीति का साधन बना लिया है।

स्विट्जरलैंड के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देकर मोदी ने यूरोप में चली बड़ी कूटनीतिक चाल

भारत और स्विट्जरलैंड की साझेदारी का असली रणनीतिक विस्तार रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी में दिखाई देता है। दोनों पक्षों ने सैन्य आदान-प्रदान और रक्षा उत्पादन में नए अवसर तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। दुनिया के बदलते सामरिक और आर्थिक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति लगातार भारत की वैश्विक पहुंच को नए आयाम दे रही है। इसी व्यापक कूटनीतिक रणनीति की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्विट्जरलैंड के साथ संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में आज एक अहम कदम सामने आया। स्वि्स राष्ट्रपति गाइ पारमेलिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने प्रवास एवं गतिशीलता, युवा पेशेवरों, परिवहन प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नवाचार और स्टार्टअप सहयोग से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर रक्षा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी और वैश्विक कूटनीति तक साझेदारी का विस्तार यह संकेत देता है कि भारत-स्विट्जरलैंड संबंध अब एक नए रणनीतिक चरण में प्रवेश कर रहे हैं और मोदी की सक्रिय कूटनीति ने यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश के साथ भारत की साझेदारी को जित तेजी से व्यापक बनाया है, उसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री मोदी और गाइ पारमेलिन की मुलाकात का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत और स्विट्जरलैंड अब अपने रिश्ते को

बहु-आयामी रणनीतिक साझेदारी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद हाउस में मोदी और पारमेलिन ने व्यापार एवं निवेश, एआई, नवाचार, रक्षा उत्पादन और सैन्य आदान-प्रदान, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान-प्रौद्योगिकी तथा लोगों के बीच संपर्क सहित पूरे संबंधों की समीक्षा की। देखा जाये तो आर्थिक मोर्चे पर भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता इस रिश्ते की रीढ़ बनकर उभरा है। यह समझौता अक्टूबर 2025 में लागू हुआ था और स्विट्जरलैंड इसे भारतीय बाजार में स्वि्स कंपनियों को पहुंच और निवेश के लिए अधिक निश्चितता देने वाला कारा मानता है। स्विट्जरलैंड के अनुसार भारत एशिया में उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और देश में 330 से अधिक स्वि्स कंपनियां सक्रिय हैं। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समझौते के जरिए अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय कृषि उत्पादों, औषधियों, वस्त्रों और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए स्वि्स बाजार में अवसर बढ़ाने के साथ भारत जैव-प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में स्वि्स निवेश आकर्षित करना चाहता है। लेकिन इस साझेदारी का असली रणनीतिक विस्तार रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी में दिखाई देता है। दोनों पक्षों ने सैन्य आदान-प्रदान और रक्षा उत्पादन में नए अवसर तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। यह संकेत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्विट्जरलैंड की उच्च तकनीकी औद्योगिक



क्षमता और भारत की बढ़ती रक्षा विनिर्माण महत्वाकांक्षा मिलकर नए तकनीकी और औद्योगिक सहयोग के रास्ते खोल सकती हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में भी सहयोग अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। वाराणसी रोपवे, नोएडा के जेवर हवाई अड्डे और पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे तथा सुरंग परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मोदी ने परिवहन, गतिशीलता और आधारभूत ढांचे पर नए समझौते को आगे की साझेदारी का आधार बताया। समझौते में विद्युत वाहन, रोपवे, परिपत्र अर्थव्यवस्था, सुरंग और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों पर सहयोग शामिल है। साथ ही विज्ञान और नवाचार इस रिश्ते की दूसरी बड़ी धुरी बन रहे हैं। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्वि्स राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान के बीच समझौता दीर्घकालिक संयुक्त अनुसंधान का ढांचा तैयार करेगा। स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में नए संयुक्त शोध की शुरुआत भी प्रस्तावित है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान

के साथ समझौते के जरिए शुरुआती चरण के भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षण, तकनीकी हस्तांतरण, कार्यशालाओं और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा। मानव संसाधन के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। प्रवास एवं गतिशीलता साझेदारी के तहत पांच वर्ष तक वैध बहु-प्रवेश वीजा और प्रत्येक यात्रा में छह महीने तक ठहरने की सुविधा का प्रावधान है। छात्रों के लिए नवीकरणीय एक-वर्षीय अनुमति भी शामिल है। वहीं युवा पेशेवरों के आदान-प्रदान समझौते के तहत हर वर्ष दोनों देशों से 300-300 युवा पेशेवर भेजे जा सकेंगे, जिसे बढ़ाकर 500 तक किया जा सकता है। इसका उद्देश्य युवाओं को काम के साथ पेशेवर और भाषाई कौशल विकसित करने का अवसर देना है। यह समझौता प्रतिभा, तकनीक और पूंजी, तीनों को एक ही गलियारों में जोड़ता है। भारत को वैश्विक प्रतिभा और नवाचार नेटवर्क में प्रवेश मिलता है, जबकि स्विट्जरलैंड को भारत के विशाल प्रतिभा और बाजार आधार से जुड़ने का

अवसर मिलता है। इसके अलावा, दोनों देशों ने आगामी भारत-स्वि्स अनुसंधान प्रमुख कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की भी घोषणा की है। साथ ही वैश्विक शांति, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया जैसे संकटों पर भारत ने हर सार्थक शांति प्रयास के समर्थन की अपनी नीति दोहराई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस रिश्ते का अगला मोर्चा है। भारत में 2026 के एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के बाद स्विट्जरलैंड अगले चरण में जिनेवा एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोनों देशों की कोशिश जिम्मेदार, समावेशी और मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सहयोग बढ़ाने की है। साफ है कि यह यात्रा केवल पांच समझौतों की कहानी नहीं है। इसके पीछे भारत की रणनीति यूरोप में व्यापार, निवेश, उन्नत तकनीक और विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाओं के नए केंद्रों से संबंध मजबूत करने की है, जबकि स्विट्जरलैंड भारत को अपने एशियाई आर्थिक और तकनीकी विस्तार के महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देख रहा है। 7 अक्टूबर का भारत-ईएफटीए 'प्रॉस्पेरिटी समिट' इस पूरी कवायद को निवेश और कारोबारी परियोजनाओं में बदलने की अगली परीक्षा होगा। बहरहाल, रणनीतिक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। भारत-स्विट्जरलैंड संबंध अब घड़ियों, पर्यटन और बैंकिंग की पारंपरिक छवि से बाहर निकलकर रक्षा उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, स्टार्टअप और वैश्विक कूटनीति के नए मैदान में प्रवेश कर चुके हैं।

राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार घोषित धर्मपाल, श्रुति और प्रियंका समेत आठ नाम

लखनऊ, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए आठ उम्मीदवारों के नामों का एलान किया है। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडेय, राम प्रताप सिंह चौहान, प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। यह सूची पार्टी की रणनीति का एक अहम हिस्सा मानी जा रही है। भाजपा की ओर से जारी सूची में सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें तीन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दो अनुसूचित जाति (एससी) और तीन सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। कुल उम्मीदवारों में दो महिलाएं भी हैं। सामान्य वर्ग से दो ब्राह्मण और एक राजपूत उम्मीदवार को मौका मिला है। अन्य पिछड़ा वर्ग में एक लोधी, एक पाल और एक कुर्मी उम्मीदवार को प्रतिनिधित्व दिया गया है। धर्मपाल सिंह लोधी बिरादरी से आते हैं। वह वर्तमान में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। प्रकाश पाल संगठन में क्षेत्रीय मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। वह पाल बिरादरी से संबंध रखते हैं, जिसे ओबीसी समुदाय में गड़रिया बिरादरी माना जाता है। विद्यासागर सोनकर दलित बिरादरी से हैं। वह पार्टी के अहम पदों पर रह चुके हैं। सोनकर पूर्व विधान परिषद

पटना की सड़कों पर उतरे दारोगा अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लेने की मांग

पटना, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को एक बार फिर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस बार दारोगा अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) द्वारा मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा को रद्द करने के निर्णय को वापस लेने और घोषित परिणाम को मान्य करने की मांग कर रहे थे। दारोगा अभ्यर्थी बड़ी संख्या में जेपी गोलंबर के पास जुटे और प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। अभ्यर्थियों ने हाथों में पोस्टर लेकर आयोग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना था कि वे पिछले सात दिनों से गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं पर कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे। अभ्यर्थी मौर्य लोक की ओर से आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया।

इस दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शन के कारण आसपास के इलाकों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी बना रहा। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों के हाथों में अलग-अलग पोस्टर नजर आए।

पप्पू यादव का सरकार पर हमला

गाद नासा ने नहीं, बिहार की व्यवस्था ने जमा की

पटना, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर होने वाले खर्च को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ के स्थायी समाधान के बजाय हर साल राहत और निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पटना में सोमवार को एक प्रेस वार्ता में पप्पू यादव ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के कथित बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यदि बिहार में बारिश और बाढ़ के लिए नासा जिम्मेदार है, तो नदियों में जमा गाद के लिए भी नासा ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने सवाल किया कि एंटी-इरोशन के नाम पर एक करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं तो क्या वह पैसा भी नासा लेकर चला गया? उन्होंने कहा कि 1990 से अब तक

'अपात्र नाम हटाना भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अनिवार्य', युवाओं से की खास अपील

लखनऊ, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में अवैध रूप से दर्ज अपात्र नामों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार हटाना भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अनिवार्य है। साथ ही, सीएम योगी ने युवाओं से भी खास अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, भारत युगों से लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अपने लोकतांत्रिक विरासत की और सुदृढ़ करने का



महत्वपूर्ण प्रयास है। मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुल्लूकेट प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन आवश्यक है। उन्होंने आगे लिखा, सभी जागरूक मतदाता ध्यान रखें कि मतदाता सूची में अवैध रूप से दर्ज अपात्र नामों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार हटाना भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अनिवार्य है। सीएम योगी ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, मेरी अपील है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे प्रत्येक युवा साथी अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। आइए, शुद्ध, सशक्त और पारदर्शी मतदाता सूची के निर्माण में सहभागी बनें। मुख्यमंत्री योगी ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है, जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल देशभर में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।

भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट



- दो ओबीसी, दो एससी, तीन सामान्य वर्ग के उम्मीदवार**
- मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा का नाम नहीं**

सदस्य (एमएलसी) और मछलीशहर से पूर्व सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा, वह पार्टी के पूर्व महामंत्री भी रह चुके हैं।

नए चेहरों को मौका

इस बार भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए सभी नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने पुराने चेहरों को इस बार मौका नहीं दिया है। जिन प्रमुख नेताओं को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, उनमें अरुण सिंह, सीमा द्विवेदी, बीएल वर्मा, हरदीप सिंह पुरी, नीरज शेखर, वृजलाल, दिनेश शर्मा और गीता शाक्य शामिल हैं।

मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा का नाम भी इस सूची में नहीं है। दिनेश शर्मा वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं।

1. धर्मपाल सिंह, 2. राधाकांत ओझा, 3. प्रकाश पाल, 4. विद्यासागर सोनकर, 5. गोपी कृष्ण पाण्डेय, 6. प्रियंका सिंह रावत 7. राम प्रताप सिंह चौहान, 8. श्रुति गंगवार। भाजपा ने श्रुति गंगवार को बनाया प्रत्याशी, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की हैं बेटी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्यसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए

बरेली में चार दशकों से सियासत के धुरंधर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के इस कदम को रूहेलखंड क्षेत्र में सामाजिक संतुलन साधने, कुर्मी वोट बैंक को मजबूती से बांधे रखने और पार्टी के प्रति निष्ठावान पुराने नेतृत्व का सम्मान करने के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि भाजपा का यह फैसला महज एक सीट का नामांकन नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति की दिशा तय करने वाला मास्टरस्ट्रोक है। रूहेलखंड क्षेत्र विशेषकर बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में कुर्मी समुदाय की निर्णायक उपस्थिति है। आठ बार के सांसद रहे संतोष गंगवार इस वर्ग के सर्वमान्य चेहरे माने जाते रहे हैं।

श्रुति गंगवार को उच्च सदन भेजकर पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में टिकटों के पुनर्गठन और नई पीढ़ी को मौका देने के क्रम में संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों और स्थानीय कैडर में जो असमंजस था, पार्टी ने उसे क्रमवार दूर किया है।

वादी जज और आरोपी वकील : मुकदमे का फैसला आने में लगे 34 साल केवल एक गवाह ही पेश कर सका अभियोजन; दो बरी



प्रेमशंकर चौहान और विजय राघव ने अदालत कक्ष में प्रवेश किया और अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए अशोभनीय भाषा व गाली-गलौज की।

जज को दी थी जान से मारने की धमकी

आरोप था कि अधिवक्ताओं ने न्यायिक पत्रावली की अजी फाड़कर अपनी जेब में रख ली, डायस पर चढ़कर अभद्रता की और बाद में पीठासीन अधिकारी के चैंबर में घुसकर उनके साथ

मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में आनन-फानन में चार्जशीट तो दाखिल कर दी, लेकिन बाद में अभियोजन पक्ष 34 वर्षों की लंबी जद्दोजहद के दौरान एक गवाह ही पेश कर सका। यह इकलौता गवाह भी अदालत में अपने मूल बयानों से मुकर गया। गवाह ने जज के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी, मारपीट या पत्रावली फाड़ने की घटना से

दिनदहाड़े भूना : बिहार में वकील की हत्या

बक्सर, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। बिहार के कटिहार में दिनदहाड़े बीच बाजार अधिवक्ता गुड्डू अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली, पटेल चौक के पास हुई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना का फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक अपराधी अधिवक्ता को गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अपराधी ने बीच बाजार में अधिवक्ता को निशाना बनाया और गोली मारकर मौके से फरार हो गया। गोली लगने के बाद गुड्डू अंसारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हत्या की वजह को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं।

गंडक बाढ़ में तटबंध क्षति पर सरकार का एक्शन गोपालगंज-छपरा के सात इंजीनियर निलंबित

पटना, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। बिहार में गंडक नदी में आई बाढ़ के बाद सरकार ने तटबंधों की सुरक्षा और क्षति के मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जल संसाधन विभाग ने गोपालगंज और छपरा में तटबंध क्षतिग्रस्त होने तथा उसके बाद अपेक्षित कार्रवाई में लापरवाही और शिथिलता बरतने के आरोप में सात इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

विभाग की ओर से जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, गोपालगंज बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल से जुड़े तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें तत्कालीन कार्यपालक अभियंता मो. साजिद इकबाल, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी मो. जावेद अंसारी और तत्कालीन कनीय अभियंता विकास कुमार शामिल हैं। तीनों पर तटबंध क्षतिग्रस्त होने के बाद अपेक्षित

अयोध्या, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। रामनगरी अयोध्या पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पहले रामलला के दरबार में माथा टेका। इसके बाद रानेपाली स्थित उदासीन ऋषि संगत आश्रम पहुंचे। यहां निष्ठावान पुराने नेतृत्व का सम्मान करने के लिए गुरु पर्व महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित श्रीनारायण राम संस्कृत विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। आश्रम परिसर में संत सम्मेलन के साथ जनसभा का आयोजन किया गया। रक्षामंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी।

संस्कृत महाविद्यालय की और व्यापक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखें

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संस्कृत शिक्षा की परंपरा को श्रीनारायण संस्कृत महाविद्यालय की ओर व्यापक एवं विस्तृत करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना होगा। नवनिर्मित भवन केवल विद्यार्थियों के आवास की सुविधा नहीं देगा, बल्कि भविष्य में संस्कृत शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो सकेगा। संस्कृत विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे जीवन का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। संस्कृत पढ़ने का संकल्प लेना सौभाग्य की बात है। देवभाषा संस्कृत में ज्ञान, विज्ञान और अथात्स की विशाल परंपरा मौजूद है। उन्होंने विद्यार्थियों से संस्कृत के प्रति अपना समर्पण बनाए रखने



पीढ़ियों तक भारतीय परंपराओं पहुंचाने के संकल्प का प्रतीक है नया भवन

उन्होंने कहा कि आज का दिन आश्रम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। नवनिर्मित भवन को देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। यह भवन सामान्य निर्माण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक भारतीय परंपराओं और ज्ञान को पहुंचाने के संकल्प का प्रतीक है। संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा बताते हुए राजनाथ ने कहा कि इसके विस्तार में जाएं तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इसमें ज्ञान-विज्ञान की समृद्ध परंपरा समाहित है। सरकार ने संस्कृत के अध्ययन को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया है। संस्कृत और आधुनिक शिक्षा का समन्वय नई पीढ़ी को परंपरा से जोड़ने के साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करेगा। परंपरा को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उसे केवल याद करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को उसका ज्ञान और संस्कार देना है।

रामलीला मैदान में रावण का पुतला बनाते समय विस्फोट, पांच घायल, दो दीवारें गिरीं

गाजियाबाद, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह रामलीला मैदान में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सामुदायिक केंद्र भवन के एक बड़े हॉल में आचाक आग लग गई। प्रारंभिक सूचना में आग पटाखों की दुकानों में लगने की बात सामने आई थी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। हालांकि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पता चला कि आग किसी पटाखे की दुकान में नहीं, बल्कि रामलीला मैदान के पीछे स्थित सामुदायिक केंद्र के बड़े हॉल में लगी थी। हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें आगे जीटीबी अस्पताल रेफर किए जाने की जानकारी मिली है। फायर विभाग के अनुसार, सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 9:26 बजे फायर स्टेशन साहिबाबाद के कंट्रोल रूम को रामलीला मैदान, शनि चौक स्थित पटाखों की दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी।

गैंगस्टर में कुर्क संपत्ति रिलीज से इन्कार पर डीएम को मामला कोर्ट भेजना जरूरी
प्रयागराज, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क संपत्ति डीएम रिलीज करने से इन्कार करते हैं तो उन्हें मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ संबंधित कोर्ट में भेजना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने डीएम का आदेश रद्द कर मामले को नए सिरे से तय करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ के तहत 22 जुलाई 2025 को कुर्क की गई थीं। याची ने उसे रिलीज करने के लिए आवेदन किया। डीएम ने नौ मार्च 2026 को आवेदन खारिज कर दिया था।

शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा : शिक्षा मंत्री का आवास घेरा, सड़क पर लेटे; पुलिस से धक्कामुक्की

लखनऊ, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। 68500 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के मामले को लेकर सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सीटी बजाकर और नारेबाजी कर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया।

अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश में ओबीसी दिव्यांग अभ्यर्थियों के परिणाम में संशोधन कर नियुक्ति देने की बात कही गई है। उनके मुताबिक, आयोग ने 150 में से 60 अंक यानी 40 प्रतिशत के आधार पर परिणाम संशोधित करने और नियुक्ति देने के साथ आरक्षण विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ

कार्रवाई की बात कही है। अभ्यर्थियों ने इसी आदेश के अनुपालन की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने 'संदीप भैया न्याय करो', 'है हक हमारा आरक्षण, हम लेकर रहेंगे आरक्षण' और 'बाबू कल्याण सिंह अमर रहे' सहित कई नारे लगाए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाकर हिरासत में लिया और ईको गार्डन भेज दिया।

मंगलवार को शिक्षा मंत्री से वार्ता प्रस्तावित
धरने का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तुफान सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से शिक्षा मंत्री से वार्ता की गई है। उनके अनुसार, मंगलवार को दोपहर 12 बजे के बाद अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल और शिक्षा मंत्री के बीच वार्ता प्रस्तावित है। वार्ता में मांगों पर चर्चा के बाद अभ्यर्थी आगे की रणनीति तय करेंगे।

गंडक बाढ़ में तटबंध क्षति पर सरकार का एक्शन गोपालगंज-छपरा के सात इंजीनियर निलंबित



कार्रवाई में लापरवाही और शिथिलता बरतने का आरोप है। देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक, छपरा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल में तटबंध क्षतिग्रस्त होने के मामले में चार इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई है। इनमें कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार प्रभाकर, अवर प्रमंडल मुख्यालय मुख्य अभियंता, सिंचाई पदाधिकारी सुनील कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी बिनोद कुमार और कनीय अभियंता चंद्रशेखर कुमार शामिल हैं। छपरा से जुड़े

भत्ता देय होगा। इसी तरह रविवार देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक, छपरा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल में तटबंध क्षतिग्रस्त होने के मामले में चार इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई है। इनमें कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार प्रभाकर, अवर प्रमंडल मुख्यालय मुख्य अभियंता, सिंचाई पदाधिकारी सुनील कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी बिनोद कुमार और कनीय अभियंता चंद्रशेखर कुमार शामिल हैं। छपरा से जुड़े

इन चारों अधिकारियों को भी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इन्हें भी नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। दरअसल, सितंबर के अंतिम सप्ताह में नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई थी। इससे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। नदी के बढ़े जलस्तर के कारण कई स्थानों पर तटबंधों पर दबाव बढ़ा और क्षति की स्थिति सामने आई।

सलमान खान की 'मातृभूमी' को

मिली सरकार से हरी झंडी

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म की घोषणा 'बैटल ऑफ गलवान' के तौर पर हुई थी और इस साल की शुरुआत में इसका नाम बदलकर 'मातृभूमि' कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी भारत और चीन के बीच 2020 में हुए टकराव पर आधारित है। वहीं, हाल ही में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है, इसलिए रक्षा मंत्रालय को फिल्म में चीन से जुड़े कुछ सीन्स से आपत्तियां थीं, जिसकी वजह से फिल्म में देरी देखने को मिली। हालांकि, अब फिल्म को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और फिल्म इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

रिपोर्टर्स के मुताबिक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मेकर्स द्वारा दिए 'मातृभूमि' के नए वर्जन से कोई आपत्ति नहीं है। जिसके चलते इस वॉर-ड्रामा फिल्म के लिए एनओसी दे दी गई है। एनओसी मिलने के बाद अब ये फिल्म इस साल के आखिरी में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है, हालांकि इसकी ऑफिशियल डेट अभी तक सामने नहीं आई है।

बाली से स्ट्रेंचर पर मुंबई लाई गई नुसरत भरूचा

इशारों में करती दिखीं बातें



बाली में एक्सीडेंट की वजह से 'प्यार का पंचनामा' एक्ट्रेस नुसरत भरूचा काफी मुश्किल घड़ी से गुजर रही हैं। इस हादसे में एक्ट्रेस की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी सर्जरी मुंबई के अस्पताल में होगी। एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस का अब पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें वह स्ट्रेचर पर लेटी हैं और उनकी हालत काफी गंभीर लग रही है। बाली से नुसरत भरूचा को सर्जरी के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई लाया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो

ओलिविया डीन: कानूनी पचड़े में फंसीं ग्रेमी अवॉर्ड विजेता सिंगर

मशहूर ब्रिटिश सिंगर ओलिविया डीन पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा है। यह आरोप उनके गाने 'आई हैव सीन इट' को लेकर लगाया गया है। इसे लेकर वे कानूनी मुसीबत में घिर गई हैं। ओलाविया पर आरोप है कि उन्होंने बिल विथर्स के गाने 'जस्ट द टू ऑफ अस' की नकल की है। सिंगर ओलिविया डीन पर एक म्यूजिक पब्लिशर ने आरोप लगाया है कि 'आई हैव सीन इट' गाने में बिल विथर्स के 1981 के मशहूर गाने 'जस्ट द टू ऑफ अस'के कुछ हिस्सों की नकल की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, मैटी म्यूजिक ग्रुप ने केलिफोर्निया में एक मुकदमा दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि डीन के 2025 के गाने और दिवंगत गायक के हिट गाने में काफी समानताएं हैं। बता दें कि विथर्स के म्यूजिक कैटलॉग के पब्लिशिंग अधिकार मैटी म्यूजिक ग्रुप के पास हैं।

रिपोर्ट के को मिले अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, पब्लिशर का दावा है कि दोनों गानों के बीच की समानताएं साफ और नजरअंदाज न की जा सकने वाली हैं। अपनी शिकायत में मैटी म्यूजिक ग्रुप ने तर्क दिया कि म्यूजिक के जो हिस्से एक जैसे थे, वे इतने ज्यादा मिलते-जुलते थे कि उन्हें महज इन्फोफ़ाक या स्वतंत्र रूप से बनाई गई रचना नहीं माना जा सकता।

अब एक्ट्रेस ने पहली बार इन तमाम बातों पर खुलकर जवाब दिया है। कोमल रानी ने 2 अक्टूबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया।

उन्होंने बिना किसी का नाम लिए उन लोगों पर निशाना साधा, जो गोविंदा के साथ उनके रिश्ते को लेकर बयानबाजी कर रहे



साल के आखिरी में रिलीज है सकती है 'मातृभूमी'

रिपोर्टर्स के मुताबिक, सलमान खान 13 नवंबर पर नजर बनाए हुए हैं। उनका ये मानना है कि दीवाली के बाद का समय जब सब फेस्टिव मूड में होंगे जब इस फिल्म को रिलीज करना ठीक होगा। हालांकि, सेंसर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। मेकर्स जल्द ही फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशन (सीबीएफसी) के पास जमा करेंगे। अगर इस फिल्म को सीबीएफसी की तरफ से मंजूरी मिल जाती है और ये प्रोसेस इसी महीने पूरी हो जाती है, तो सलमान और उनकी टीम 'मातृभूमी' को इसी साल 13 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज कर सकते हैं।

हैदराबाद में फैस की भीड़ ने फरहाना भट्ट को घेरा



गुडामलकापुर में भारी भीड़ देखी गई, क्योंकि फैस रियलिटी टीवी स्टार फरहाना

राधिका मदान को बॉलीवुड में आउटसाइडर होने का क्यों सता रहा है डर ?

कुछ डर ऐसे होते हैं, जिन पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। पटाखा और अंग्रेजी मीडियम समेत कई फिल्में कर चुकी राधिका मदान के लिए आज भी आउटसाइडर होने का डर सबसे बड़ा है। आज के दौर में कलाकारों के लिए क्या सबसे चुनौतीपूर्ण है, इस सवाल का जवाब देते हुए राधिका ने कहा, कई लोग अभिनय को कठिन मानते हैं, लेकिन मेरे लिए वह चुनौतीपूर्ण नहीं है। अगर सही तरह की स्क्रिप्ट आपको ऑफर हो रही हैं। मेरी दिक्कत आउटसाइडर वाली है, जो उनके साथ होता है।

मन में एक डर हमेशा रहता है कि मैं अपने काम के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही हूं, क्योंकि फिर मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। राधिका ने अपने डर के बारे में बात करते हुए आगे कहा, हर परफार्मेंस पर मुझे चौका और छक्का ही मारना होगा। मेरा यहां कोई नहीं बैठा है, जो मुझे संभाल लेगा। अगर मैंने दो-तीन फिल्मों में मध्यम स्तर की परफार्मेंस दे दी तो कोई यह बोलने वाला नहीं है कि बेठा कोई बात नहीं, एक और मौका देता हूं, अच्छा कर रही हो, बेहतर हो जाओगी। यही डर मेरे भीतर से नहीं जा रहा है। राधिका मदान ने

लातों से मारा

बाल पकड़कर घसीटा, मैं कांप गई जब देखा... रिलेशनशिप पर छलका काजल राघवानी का दर्द

भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस काजल राघवानी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। काजल ने अपने करियर में कई शानदार भोजपुरी फिल्में दी हैं। वहीं, बीते दिनों काजल को रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में देखा गया। वहीं, अब काजल 'राइज एंड फॉल 2' में नजर आ रही हैं। काजल ने शो के दौरान एक बार फिर से अपने एक्स रिलेशनशिप पर बात की है और मारपीट का खुलासा किया, जिसने उनके फैस को हैरान कर दिया।

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी आजकल 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में एक कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही हैं। हाल ही के एक एपिसोड में, काजल ने अनीश भगत के साथ बातचीत के दौरान अपनी जिंदगी के उस बुरे रिश्ते के बारे में बताया, जिसने उन्हें न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी तोड़कर रख दिा था।

पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी के कायल हुए सलमान खान

बोले- आपके साथ उड़ान भरना मेरा सौभाग्य होगा

बुधवार को दुबई से तेलअवीव जा रही फ्लाइट में ओमानी को पायलट ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर पर हमला कर दिया और प्लेन को क्रेश करने की कोशिश की। लेकिन उस दौरान पायलट स्मित मच्छार ने जिस तरह की बहादुरी दिखाई, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। सलमान खान ने भी स्मित मच्छार के लिए एक्स पर पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में सलमान खान स्मित मच्छार की तारीफ करते नजर आए। सलमान खान ने अपने पोस्ट पर लिखा- कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सलाम करते हैं। आपके साथ उड़ान भरना मेरा सौभाग्य होगा। शाबाश ब्रो। कैप्टन स्मित मच्छार। सलमान खान के इस पोस्ट पर लोगों ने स्मित मच्छार की तारीफ की है।

एक यूजर ने लिखा- वदीं पर लगे बैज से ज्यादा, सीने में धड़कता देशप्रेम मायने रखता है। कैप्टन साहब, आपने साबित कर दिया कि आसमान भी अपनों के आगे झुकता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- एक शर्मिंदगी वाला पोस्ट भी करो, दूसरे पायलट के लिए। एक ने कहा- इट्स डन ब्रो के बाद अब है शाबाश ब्रो। एक ने लिखा- हमला होने के बाद स्मित हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की जान बचना जरूरी समझा। ये असली हीरो हैं।



'चुट्टामल्ले' गाने के एआई वीडियो में

एनटीआर और जाहनवी के चेहरे बिगड़े हुए दिख रहे हैं



'यंग टाइगर' एनटीआर और बॉलीवुड की खूबसूरत जाहनवी कपूर की जोड़ी वाली पैन-इंडिया फ़िल्म 'देवरा' (निर्देशन: कोराताला शिवा) ने बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाए हैं। तारक ने 'देवरा' फ़िल्म से धूम मचा दी और अपने सोलो करियर में 500 करोड़ रुपये की कमाई की। इस फ़िल्म के लिए अनिरुद्ध रविचंद्रर के दिए गाने चार्टबस्टर साबित हुए। खासकर मेलोडी ट्रैक चुट्टामल्ले के रिलीज़ होने के बाद से ही इसके म्यूज़िक को रिकॉर्ड व्यूज़ मिले हैं।

लेकिन अब इस ब्लॉकबस्टर गाने को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में एक नई बात सामने आई है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। गाने के ओरिजिनल सीन को डिजिटल रूप से बदलकर हीरो और हीरोइन का एक भ्रामक रूप तैयार किया गया है। मॉर्फिंग से बनाए गए इस एआई वीडियो ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है।

कुछ डिजिटल क्रिएटर्स ने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनटीआर और जाहनवी कपूर के हाव-भाव को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। उन्होंने ओरिजिनल गाने के बिना रोमांटिक सीन, गलत क्लिप और गुमराह करने वाले वीडियो बनाकर इंटरनेट पर फैला दिए हैं।

इन मॉर्फिंग वीडियो को देखकर आम लोगों और फ़ैन्स को ऐसा लगा जैसे वे सच में फ़िल्म का हिस्सा हों। समझ न पाने के कारण वे उलझन और बेचैनी महसूस करने लगे। ऐसी हरकतों से सेलिब्रिटीज़ की निजी प्रतिष्ठा और सम्मान को गंभीर नुकसान पहुँचता है। एनालिस्ट और फ़ैन्स इस बात से हैरान और परेशान हैं।

'नई नवेली' का प्रमोशन करने पटना पहुंचीं यामी गौतम



बॉलीवुड को भी अब समझ आ गया है कि बॉक्स ऑफ़िस का असली 'भौकाल' तो पटना से ही सेट होता है। हाल ही में 'वन' की टीम ने यहां गदर काटा था, और अब अपनी अपकॉमिंग हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'नई नवेली' का बज हाई करने बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम पटना पहुंच गईं। फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत यामी गौतमने पटना की रक्षक मानी जाने वाली 'मां बड़ी पटन देवी' के आशीर्वाद के साथ की। मंदिर के विजुअल्स में यामी ग्रीन कलर के बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल सूट में नजर आ रही हैं, जिसके ऊपर उन्होंने रेड और ऑरेंज कलर की माता की चुनरी ओढ़ी हुई है।

मंदिर के अंदर हाथ जोड़े और पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन यामी का यह नज़ारा भरा अवतार इंटरनेट पर फैस का दिल जीत रहा है। माता रानी के दर्शन के बाद यामी का

स्पिरिचुअल टूर पटना के गुरुद्वारे भी पहुंचा। वहां भी एक्ट्रेस ने सादगी भरे अंदाज़ से फैस को स्माइल दिया और बाद में मत्था टेका। आशीर्वाद लेने के बाद यामी सीधे अपने फैस से रूबरू होने पटना के फेमस पीएनएम मॉल पहुंचीं, जहां उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मॉल के एस्केलेटर पर अपनी सिक्वोरिटी, टीम और बाउंसर्स के बीच घिरीं यामी ने लोगों को स्माइल देकर ग्रीट किया। साथ ही 'नई नवेली' फिल्म देखने की गुज़ारिश भी की। फिल्म में यामी गौतम के अलावा अहिनाथ एम।

कोठारे, अनुराग ठाकुर, सुनीता राजवर, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुस्मिता मुखर्जी और प्रतीक पंचौरी आदि हमर किरदारों में हैं। यामी गौतम की यह फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को दशहरे से पहले सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

देते हुए कहा कि वह और गोविंदा साथ काम कर रहे हैं और आगे भी साथ नजर आएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी को इससे परेशानी है तो वह जल सकता है।

कोमल ने इन एक्ट्रेस पर साथ निशाना! इसके साथ ही एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री की कुछ एक्ट्रेसों पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि जिनका करियर अब पहले जैसा नहीं रहा, वे दूसरों के विवादों में दखल देकर सुखियों में बने रहने की कोशिश कर रही हैं। कोमल ने ऐसे लोगों को अपनी हद में रहने की सलाह भी दी।

कोमल की लोगों से अपील बता दें, कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी कथित तौर पर कोमल रानी के साथ उनके रिश्ते को लेकर तंज कस चुकी हैं। वहीं, हाल के दिनों में दिव्या खोसला और कश्मीरा शाह ने कोमल को लेकर नाराजगी जताई थी। बहरहाल, अब कोमल ने लोगों से अपील की है कि उनका नाम गोविंदा के साथ जोड़ना बंद किया जाए। फिलहाल दोनों अपनी फिल्म 'रूपा' को लेकर भी चर्चा में हैं।